भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3226
दिनांक 20 मार्च, 2025

इथेनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना

†3226.**श्री अनुराग शर्मा:**
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री भोजराज नाग:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री रमेश अवस्थी:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्री आलोक शर्मा:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री खगेन मुर्मु:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इथेनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए किस विशिष्ट समय-सीमा पर विचार किया जा रहा है;
(ख) उच्च इथेनॉल मिश्रणों के साथ संभावित वाहन अनुकूलता मुद्दों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;
(ग) भारत के कृषि क्षेत्र विशेषकर गन्ना और मक्का उत्पादन को इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य में वृद्धि किस प्रकार प्रभावित करेगी;
(घ) किसानों और इथेनॉल उत्पादकों को उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाएगा;
(ड.) सरकार इथेनॉल उत्पादन और खाद्य आपूर्ति शंखलाओं के बीच मक्का और गन्ना आवंटन को किस प्रकार संतुलित करने की योजना बना रही है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके; और
(च) कर्नाटक के किसानों को इस कार्यक्रम से अब तक किस प्रकार का लाभ हुआ है और कर्नाटक के किसानों से भविष्य में क्या खरीद की योजना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018, वर्ष 2022 में यथासंशोधित, में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 से घटाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य जून, 2022 में अर्थात् ईएसवाई 2021-22 के दौरान निर्धारित समय से पाँच माह पहले ही प्राप्त कर लिया। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण ईएसवाई 2022-23 में और बढ़कर 12.06%, ईएसवाई 2023-24 में 14.60% तथा ईएसवाई 2024-25 में दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक 17.98% हो गया। अब तक, सरकार द्वारा 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने हेतु निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) एक अन्तर मंत्रालयी समिति द्वारा तैयार भारत में एथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप 2020-25 के अनुसार, 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) के उपयोग के परिणामस्वरूप ई10 के लिए डिजाइन और ई20 के लिए कैलिब्रेटेड चार पहिया वाहनों के लिए ईंधन दक्षता में सीमान्त ह्रास आता है। सोसायटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (एसआईएएम) ने समिति को बताया था कि मिश्रित ईंधन के कारण आयी दक्षता ह्रास को इंजन हार्डवेयर और ट्यूनिंग में बदलाव करके कम किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि ई20 ईंधन से वाहन के प्रदर्शन, इंजन घटकों के वेयर, या इंजन ऑयल में खराबी जैसी कोई बड़ी समस्या नहीं पायी गई।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति राष्ट्रीय जैवईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) द्वारा घोषित अधिशेष चरण के दौरान खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। यह नीति में मकई, कसावा, सड़े आलू जैसे फीडस्टॉक, टूटे चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, मक्का, गन्ना रस और शीरा, कृषि अवशेष (चावल की भूसी, कपास का डंठल, भुट्टे, चूरा, खोई इत्यादि) को भी प्रोत्साहित और बढ़ावा देती है। एथेनॉल उत्पादन के लिए एकल फीडस्टॉक के उपयोग की सीमा वार्षिक आधार पर परिवर्तित होती है और उपलब्धता, लागत, आर्थिक व्यावहार्यता, बाजार माँग और नीतिगत प्रोत्साहन जैसे घटकों द्वारा प्रभावित होती है। एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना रस, इसके उपोत्पादों, मक्का आदि से किसी भी प्रकार का विपथन को सुसंगत हितधारकों के साथ सावधानीपूर्वक कैलीब्रेट किया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2014 से ईबीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने के निमित्त किसानों और एथेनॉल उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें एथेनॉल उत्पादन हेतु फीडस्टॉक का विस्तार करना, एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था लागू करना, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी की दर कम करके 5% करना, एथेनॉल की अंतर्राज्यीय और अंतर-राज्य ढुलाई को सुव्यवस्थित करने हेतु उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम में संशोधन करना, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा एथेनॉल अधिप्राप्ति प्रक्रिया का सरलीकरण, पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 से घटाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 किया जाना, शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2018-22 के दौरान सरकार ने शीरे और खाद्यान्न दोनों से एथेनॉल उत्पादन करने के लिए एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न एथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाओं (ईआईएसएस) को आरंभ किया है। समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (डीईपीज) के साथ ओएमसीज द्वारा दीर्घकालिक उठान करार (एलटीओएज) पर हस्ताक्षर भी किया गया था।

(च) ईएसवाई 2023-24 (नवम्बर, 2023 से अक्टूबर, 2024) के दौरान ओएमसीज ने 679 करोड़ लीटर एथेनॉल की अधिप्राप्ति की है जिसमें से 53.8 करोड़ लीटर की आपूर्ति कर्नाटक में स्थित आसवनियों द्वारा की

गई थी। चालू ईएसवाई 2024-25 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज को 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल आवंटित किया गया जिसमें से 159.3 करोड़ लीटर कर्नाटक में स्थित आसवनियों को आवंटित की गई है। इसके अलावा, ईबीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2014-15 से सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के फलस्वरूप जनवरी, 2025 तक किसानों, जिसमें कर्नाटक राज्य के किसान भी शामिल हैं, को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का शीघ्र भुगतान किया गया है।

****